दक्षिण एशिया की भौगोलिक और आर्थिक समानताओं का उपयोग लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है - लोक सभा अध्यक्ष

ढाका, 30 जनवरी, 2016 : सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति के बारे में आज ढाका में आयोजित दक्षिण एशियाई अध्यक्ष शिखर सम्मेलन के प्रारम्भिक सत्र में बोलते हुए लोकसभा अध्यक्ष, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने कहा कि दक्षिण एशिया क्षेत्र, जो विश्व के सर्वाधिक आबादी वाले क्षेत्रों में से एक है, में विकास की अपार संभावनाएं हैं; इसके साथ हीइन लक्ष्यों को प्राप्त करने में इसके सामने अनेक चुनौतियाँ भी हैं । उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्रीय संसदों के सदस्य और अध्यक्ष होने के नाते हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश के लोगों के लिए ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के लिए इन चुनौतियों को अवसरों में बदलें ।

यह टिप्पणी करते हुए कि इस शिखर सम्मेलन के एजेंडा से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को गरीबी और भुखमरी का अंत करने और विश्व को सतत और समावेशी विकास के पथ पर अग्रसर करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराने का अनूठा अवसर मिला है, श्रीमती महाजन ने कहा कि सतत विकास के वृहत्त उद्देश्य क्षेत्रीय संपर्क और क्षेत्रीयसहयोग के मुद्दों के साथ जुड़े हुए हैं। दक्षिण एशिया का न केवल साँझा इतिहास है बल्कि सांझी सांस्कृतिक विरासत भी है। इसलिए, दक्षिण एशिया की भौगोलिक और आर्थिकसमानताओं का उपयोग पूरे क्षेत्र के लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए किया जा सकता है ।

श्रीमती महाजन ने इस बात की सराहना की कि भारत के इस रुख कि सार्वभौमिक एजेंडा सांझी किन्तु पृथक जिम्मेदारियों के सिद्धांत पर आधारित विविधतापूर्ण एजेंडाहोना चाहिए, का संयुक्त राष्ट्र विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन के निष्कर्ष दस्तावेज में समर्थन किया गया है। जहाँ भारत अपने देशवासियों के लिए सतत विकास कोबढ़ावा देने की अपनी वचनबद्धता और वैश्विक संसाधनों को कायम रखने के कार्य में अपनी भूमिका निभाने के बारे में गंभीर है, वहीँ विकासशील देशों को अधिक अंतर्राष्ट्रीयवित्तीय और प्रौद्योगिकीय संसाधन उपलब्ध कराना भी उतना ही आवश्यक है। इस सन्दर्भ में उन्होने इस बात पर जोर दिया कि विश्व के विकसित देशों को सतत उत्पादन और उपभोग पैटर्न की दिशा में तेजी से प्रगति करने का मार्ग प्रशस्त करना होगा। श्रीमती महाजन ने इस बात को दोहराया कि भारत प्राचीन काल

से ही मानता आया है कि प्रकृति के संरक्षण के बिना सतत विकास नहीं हो सकता। तदनुसार स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही भारत सतत विकास के पथ पर अग्रसर रहा है। आरम्भ से ही हम गरीबी को दूर करने के सपने को साकार करने की कोशिशें करते रहे हैं और अब हमारी बात सच साबित हुई है क्योंकि इसी मुद्दे को सतत विकास लक्ष्यों में सर्वत्र और सभी रूपों में गरीबी का अंत करने की सतत विकास लक्ष्यों की वचनबद्धता के रूप में शामिल किया गया है। इसी तरह खाद्य सुरक्षा, बेहतर शिक्षा, महिला पुरुष समानता आदि जैसे मुद्दों को भी भारत के विकास संबंधी एजेंडा में हमेशा उच्च प्राथमिकता दी गई है।

इस सन्दर्भ में उन्होंने समावेशिता और सामाजिक प्रगति को बढ़ावा देने के लिए भारत में हाल ही में शुरू की गई कुछ योजनाओं का उल्लेख किया। 'जन धन योजना'अथवा 'वित्तीय समवेशिता संबंधी राष्ट्रीय मिशन', का उद्देश्य प्रत्येक घर के लिए एक बैंक खाता सुनिश्चित करना है और लोगों को वित्तीय दायरे में शामिल करके उन्हेंअधिकार देना है। 'बेटी बचाओ/बेटी पढ़ाओ' अथवा बेटियों के संरक्षण और उन्हें शिक्षित करने की योजना से उन्हें सभी विकास योजनाओं का केंद्र बनाया गया है । श्रीमतीमहाजन ने कहा कि मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया और डिजिटल इंडिया कुछ ऐसी अन्य योजनाएं हैं जिनसे सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलेगी ।

श्रीमती महाजन ने यह राय भी व्यक्त की कि प्रातिनिधिक संस्था होने के नाते संसदें सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। सततविकास लक्ष्यों पर अधिक ध्यान देकर तथा सरकार के नेतृत्व में कार्यान्वित की जा रही विकास प्रक्रिया में सभी संबंधित पक्षों करके संसदों की निगरानी संबंधी और विधायी भूमिका को और मजबूत बनाये जाने की जरूरत है।